DD FREE DISH: THE SET-TOP BOX COULD BE ON ITS WAY OUT

India's push to integrate satellite tuners directly into television sets could fundamentally change how millions of households access DD Free Dish.

The Standing Committee on Communications and Information Technology has called on the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) to demonstrate tangible progress in its plan to make DD Free Dish accessible through televisions equipped with built-in satellite tuners.

The government has informed Parliament that major television manufacturers have begun introducing models compliant with BIS specification IS 18112:2022, which enables integrated satellite reception. If widely adopted, the technology could eliminate the need for a separate set-top box for Free Dish households.

The shift is significant for a platform estimated to reach more than 49 million households, particularly across rural, remote and economically underserved regions.

डीडी फ्री डिशः सेट टॉप बॉक्स का इस्तेमाल शायद बंद हो जाए

भारत सरकार टेलीविजन सेट में ही ट्यूनर लगाने की कोशिश कर रही है। इससे लाखों घरों में डीडी फ्री डिश देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है।

सूचना और संचार तकनीकी पर संसद की स्थायी समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से कहा है कि वे 'डीडी फ्री डिश' को बिल्ट–इन सैटेलाइट ट्यूनर वाले टेलीविजन पर उपलब्ध कराने की अपनी योजना में ठोस प्रगति दिखायें।

सरकार ने संसद को सूचित किया है कि टीवी बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने बीआईएस विशिष्टकरण IS 18112:2022 के मुताबिक मॉडल बनान शुरू कर दिया है जिसमें सैटेलाइट रिसेप्शन की सुविधा पहले से ही मौजूद है। अगर इस तकनीकी को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, तो 'फ्री डिश' का इस्तेमाल करने वाले घरों को अलग से सेट–टॉप–बॉक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह बदलाव उस प्लेटफॉर्म के लिए अहम है जिसके 4.9 करोड़ घरों तक पहुंचने का अनुमान है–खासकर ग्रामीण, दूर–दराज और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में।

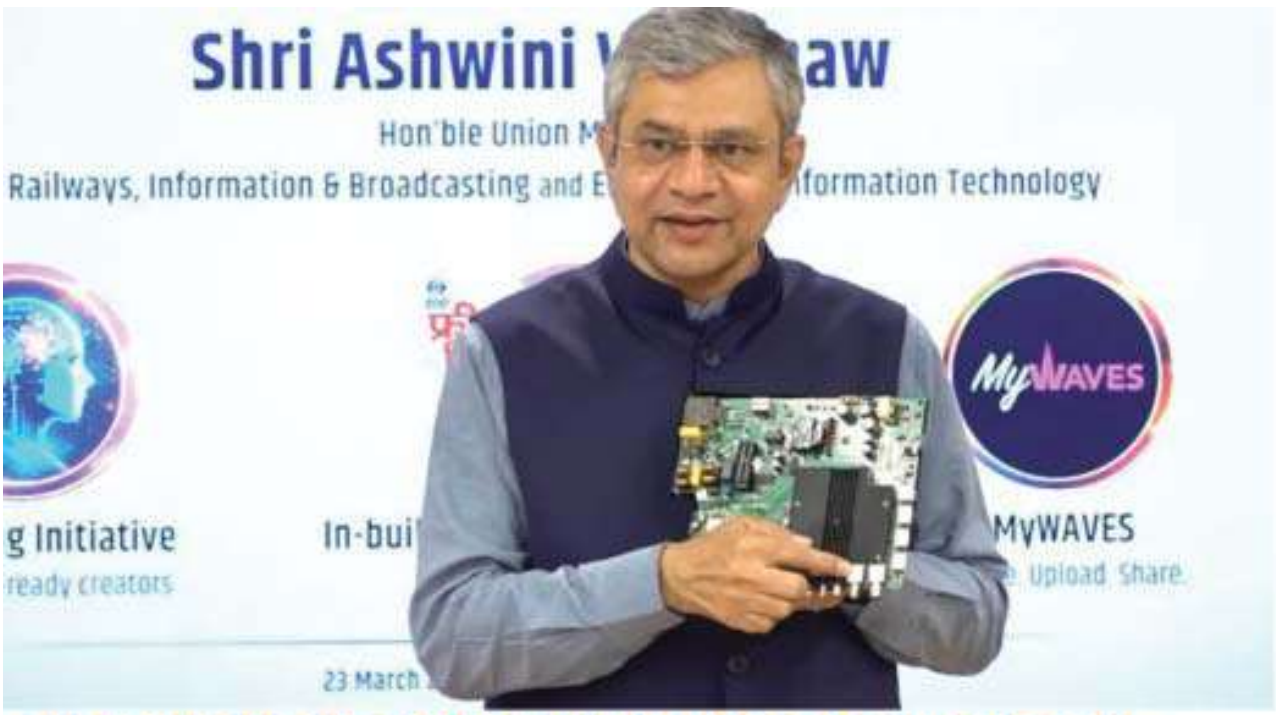

NO MORE SET-TOP BOXES: DIRECT ACCESS TO DD FREE DISH, MIB BETS ON BUILT-IN TV TUNERS

FROM SET-TOP BOXES TO INTEGRATED RECEPTION

The proposed model represents a fundamental change in the way free-to-air satellite television is delivered. Instead of relying on a separate DTH receiver, consumers would need only a compatible television and satellite antenna to access DD Free Dish, without a monthly subscription.

The platform currently offers a substantial bouquet of television and radio services, including Doordarshan channels, private channels and educational services. While the existing setup requires an initial investment for a dish antenna, MPEG-4 set-top box and related equipment, integrated satellite tuners could simplify installation and reduce hardware dependence.

The move could also complement the government's efforts to extend broadcasting services into regions where terrestrial infrastructure and paid television services remain limited.

INDUSTRY ADOPTION BECOMES THE KEY TEST

The MIB has stated that prominent consumer electronics brands have already introduced television models featuring compliant integrated tuners. The transition was targeted for completion by July 2026, with most new television sets reportedly moving towards integrated satellite reception.

Prasar Bharati and Doordarshan are also working with television manufacturers and set-top-box OEMs to integrate an advanced Electronic Programme Guide (EPG) into television operating systems. Engagement with platforms such as Google TV, WebOS and Tizen could make Free Dish discovery considerably simpler, without requiring an internet connection.

However, technology availability alone will not guarantee consumer adoption.

सेट टॉप बॉक्स से एकीकृत रिसेप्शन तक

यह प्रस्तावित मॉडल 'फ्री–टू–एयर' सैटेलाइट टेलीविजन के प्रसारण तरीके में एक बड़ा बदलाव लाता है। अलग डीटीएच रिसीवर पर निर्भर रहने के बाजाय, ग्राहकों को डीडी फ्री डिश का लाभ उठाने के लिए केवल एक कम्पैटिबल टेलीविजन और सैटेलाइट एंटीना की जरूरत होगी और इसके लिए किसी मासिक सब्सक्रिप्शन की भी आवश्यकता नहीं होगी।

यह प्लेटफॉर्म अभी टेलीविजन और रडियो सेवाओं की बड़ी रेंज प्रदान कर रहा है, जिसमें दूरदर्शन चैनल, प्राइवेट चैनल और एजुकेशनल सेवा शामिल है। मौजूदा सेट टॉप के लिए डिश एंटीना, एमपीईजी–4 सेट टॉप बॉक्स और उससे जुड़े उपकरणों के लिए शुरूआती निवेश की जरूरत होती है, जबकि एकीकृत सैटेलाइट ट्यूनर इंस्टॉलेशन को आसान बना सकते हैं और हार्डवेयर पर निभरता कम कर सकते हैं।

यह कदम सरकार की उन कोशिशों में भी मदद कर सकता है जिनसे उन इलाकों में प्रसारण सेवा पहुंचायी जा सके जहां टेरस्ट्रियल संरचना और पेड टेलीविजन सेवा अभी भी सीमित है।

उद्योग द्वारा इसे अपनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी

एमआईबी ने कहा है कि जाने–माने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स ने पहले ही ऐसे टेलीविजन मॉडल पेश कर दिये हैं जिनमें जरूरी मानकों को पूरा करने वाले एकीकृत ट्यूनर लगे हैं। इस बदलाव को जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और खबर है कि ज्यादातर नये टेलीविजन सेट एकीकृत सैटेलाइट रिसेप्शन की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रसार भारती और दूरदर्शन, टेलीविजन संचालन सिस्टम में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) को शामिल करने के लिए टेलीविजन बनाने वाली कंपनियों और सेट–टॉप–बॉक्स ओईएम के साथ काम कर रहे हैं। गुगल टीवी, वेबओएस और टाइजेन जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी फ्री डिश को खोजना काफी आसान हो सकता है।

हालांकि सिर्फ टेक्नोलॉजी की उपलब्धता से ही पक्का नहीं हो जाता है कि ग्राहक इसे अपनायेंगे ही।

PARLIAMENT DEMANDS MEASURABLE RESULTS

The Parliamentary Committee has now raised an important question: how many consumers are actually benefiting from the policy?

The panel has asked the Ministry to provide measurable outcomes from Prasar Bharati's engagement with television manufacturers, including evidence of increased adoption of built-in satellite tuners and the resulting expansion of DD Free Dish.

It has also cautioned against repeatedly shifting compliance deadlines, signalling that the programme must move from policy announcements to measurable implementation.

THE BIGGER OPPORTUNITY

If successfully implemented, integrated satellite reception could transform DD Free Dish from simply a free DTH platform into a built-in broadcast capability within India's television ecosystem.

Over the longer term, this could have implications beyond DD Free Dish. Built-in satellite tuners could support a broader ecosystem of free-to-air television, emergency broadcasting, educational services and public-interest communication, while reducing dependence on proprietary set-top boxes.

For television manufacturers, the technology could become a standard feature rather than a specialised capability. For broadcasters, it could create a larger addressable audience. And for consumers, particularly in rural India, it could make free satellite television almost as simple as switching on the TV.

The Parliamentary Committee's intervention therefore comes at a crucial moment. The real measure of success will not be the number of compliant television models manufactured, but how effectively those millions of screens translate into greater access, adoption and reach for DD Free Dish.■

संसद ने ठोस नतीजों की मांग की

संसदीय समिति ने अब एक सबसे अहम सवाल उठाया हैः इस पॉलिसी से असल में पूरे देशभर में कितने ग्राहकों को फायदा होने की संभावना है?

पैनल ने मंत्रालय से कहा है कि वह प्रसार भारती और टेलीविजन बनाने वाली कंपनियों के बीच हुए काम के ठोस नतीजे को बताये। इनमें इन-विल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के ज्यादा इस्तेमाल और उससे डीडी फ्री डिश के विस्तार के सबूत भी शामिल होना चाहिए।

इसमें नियमों के पालन की समय-सीमा बार-बार बदलने के खिलाफ चेतावनी भी दी गयी। इससे यह संकेत मिलता है कि कार्यक्रम को सिर्फ पॉलिसी की घोषणाओं से आगे बढ़कर असल में लागू करने की दिशा में बढ़ना चाहिए।

बड़ा मौका

अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो एकीकृत सैटेलाइट रिसेप्शन, डीडी फ्री डिश को एक फ्री डीटीएच प्लेटफॉर्म से बदलकर भारत के टेलीविजन इकोसिस्टम में एक इन-विल्ट ब्रॉडकास्ट क्षमता बना सकता है।

लंबे समय में, इसके डीडी फ्री डिश से कहीं ज्यादा असर हो सकते हैं। इन-विल्ट सैटेलाइट ट्यूनर फ्री-टू-एयर टेलीविजन, इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशनल सर्विस और जनहित से जुड़े संचार के एक बड़े इकोसिस्टम को सर्पोट कर सकते हैं, साथ प्रोपाइटरी सेट टॉप बॉक्स पर निर्भरता भी कम कर सकते हैं।

टीवी बनाने वाली कंपनियों के लिए, यह टेक्नोलॉजी एक खास सुविधा के बजाय एक स्टैंर्ड फीचर बन सकती है। प्रसारको के लिए इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। और ग्राहकों के लिए, खासकर ग्रामीण भारत में, इससे फ्री सैटेलाइट टीवी देखना उतना ही आसान हो सकता है जितना टीवी चालू करना।

इसलिए संसदीय समिति का दखल एक अहम समय पर हुआ है। सफलता का असली पैमाना यह नहीं होगा कि नियमों के मुताबिक कितने टेलीविजन मॉडल बनाये गये, बल्कि यह होगा कि वे लाखों स्क्रीन डीडी फ्री डिश की पहुंच, इस्तेमाल और विस्तार को कितनी असरदार ढ़ंग से बढ़ा पाते हैं।■